

छत्तीसगढ़ अधिनियम

क्रमांक 22 सन् 2020

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2020

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 1995 (क्र. 24 सन् 1995) में और संशोधन करने हेतु अधिनियम ।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हो-

अध्याय 1- प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ

- (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अधिनियम 2020 कहलायेगा ।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा ।
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

परिभाषायें

- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-
 - आयोग से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन गठित छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ।
 - सदस्य से अभिप्रेत है आयोग का, सदस्य तथा अध्यक्ष (चेयरपर्सन) सम्मिलित है ।
 - अनुसूचित जनजातियों से अभिप्रेत है ऐसी जनजातियाँ या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या उनमें के यूथ जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है ।

अध्याय 2- राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग

- (1) राज्य सरकार एक निकाय का गठन करेगी जो छ.ग. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से ज्ञात होगा और जो इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गये कृत्यों का पालन करेगा ।
- (2) छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्र. 24 सन् 1995), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट हैं) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड

(क) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये। अर्थात्-

(क) “ छः अशासकीय सदस्य, जो अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान रखते हों, जिनमें से एक अध्यक्ष (चेयरपर्सन) होगा और एक उपाध्यक्ष (वाईस चेयरपर्सन) होगा, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

परन्तु अध्यक्ष (चेयरपर्सन), उपाध्यक्ष (वाईस चेयरपर्सन) सहित कम से कम चार सदस्य अनुसूचित जनजातियों में से होंगे।”

(ख) आयुक्त, जनजाति विकास छत्तीसगढ़।

अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें

4. (1) “अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य, उस तारीख से, जिस पर वह अपना पद ग्रहण करता है, राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।”
- (2) अनुमोचित दिवालिया हो जाता है।
- (क) अनुमोचित दिवालिया हो जाता है।
- (ख) किसी ऐसे अपराध के लिये, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है, दोष सिद्ध हो जाता है और कारावास में दंडादिष्ट किया जाता है।
- (ग) विकृतचित्त हो जाता है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाता है।
- (घ) कार्य करने से इंकार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है।
- (ङ) आयोग से अनुपस्थित रहने की अनुमति अभिप्राप्त किये बिना आयोग के लगातार तीन सम्मिलनों से अनुपस्थित रहता है, या
- (च) राज्य सरकार की राय में अध्यक्ष या सदस्य की हैसियत का ऐसा दुरुपयोग करता है जिससे कि उस व्यक्ति का पद पर बना रहना अनुसूचित जनजातियों के हित या लोकहित के लिये अपायकर हो गया है।
- (3) परन्तु किसी व्यक्ति को इस खण्ड के अधीन तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक कि उसे उस मामले में सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया गया है।
- (4) उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा होने वाली रिक्त को नया नाम निर्देशन करके भरा जायेगा तथा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति अपने पूर्ववर्ती की शेष अवधि तक पद धारण करेगा।
- (5) अध्यक्ष तथा सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और सेवा संबंधी निबंधन तथा शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि विहित किया जाये।

आयोग के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी

5. (1) राज्य सरकार आयोग का एक सचिव नियुक्ति करेगी तथा ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों

की व्यवस्था करेगी जो कि आयोग के कृत्यों के दक्षतापूर्णता पालन के लिये आवश्यक है।

- (2) आयोग के प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को देय वेतन तथा भत्ते और सेवा संबंधी निबंधन तथा शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि विहित किया जाये।

वेतन तथा भत्तों का भुगतान अनुदानों में से किया जायेगा

6. अध्यक्ष तथा सदस्यों को देय वेतन तथा भत्तों और प्रशासनिक व्यय, अंतर्गत धारा 5 में निर्दिष्ट सचिव, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते तथा पेंशन है, का भुगतान धारा 11 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से किया जायेगा।

रिक्तियों, आदि के कारण आयोग की कार्यवाहियाँ अविधिमान्य नहीं होंगी

7. आयोग का कोई या कार्यवाही, केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि आयोग में कोई रिक्ति विद्यमान है या आयोग के गठन में कोई त्रुटि है।

प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना

8. (1) आयोग जब जितनी बार भी आवश्यक हो अपना सम्मेलन ऐसे समय तथा स्थान पर करेगा जैसा कि अध्यक्ष उचित समझे।
(2) आयोग स्वयं अपनी प्रक्रिया विनियमित करेगा।
(3) आयोग के समस्त आदेश और विनिश्चय सचिव द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

अध्याय-3 आयोग के कृत्य तथा शक्तियाँ

आयोग के कृत्य

9. (1) आयोग का यह कृत्य होगा कि वह -
(क) अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को संविधान के अधीन तथा तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन दिये गये संरक्षण के लिये हितप्रहरी आयोग के रूप में कार्य करें।
(ख) किन्हीं विशिष्ट जनजातियों या जनजाति समुदायों या ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के यूथों को संविधान (अनुसूचित जनजातियों) आदेश 1950 में सम्मिलित करने के लिये कदम उठाने के लिये राज्य सरकार को सिफारिश करना।
(ग) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिये बने कार्यक्रमों के समुचित तथा यथा समय कार्यान्वयन की निगरानी को तथा राज्य सरकार अथवा किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण के कार्यक्रमों के संबंध में जो ऐसे कार्यक्रमों के लिये जिम्मेदार है, सुधार हेतु सुझाव दे।
(घ) लोक सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिये अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण के संबंध में सलाह दें।

(ड) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करें जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जायें।

(2) आयोग की सलाह साधारणतः राज्य सरकार पर आबद्ध कर होगी तथापि जहाँ सरकार सलाह को स्वीकार नहीं करती है वहाँ वह उसके लिये कारण अभिलिखित करेगी।

आयोग की शक्तियाँ

10. आयोग को धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन अपने कृत्यों का पालन करते समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों की बाबत किसी वाद का विचारण करने वाले किसी सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ होगी अर्थात्—

(क) राज्य के किसी भी भाग में किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना।

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट करने और पेश करने की अपेक्षा करना।

(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना।

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना।

(ड) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिये कमीशन निकालना, और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाये।

अध्याय 4- वित्त, लेखा संपरीक्षा

राज्य सरकार द्वारा अनुदान

11. (1) राज्य सरकार विधान सभा द्वारा किये गये सम्यक विनियोग के पश्चात् आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशियों का संदाय करेगी जैसा कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये उपयोग में लाई जाने के लिये उचित समझे।

(2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिये जितना राशि उचित समझे उतनी राशि का व्यय कर सकेगा और ऐसी धनराशि के उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेय व्यय के रूप में माना जायेगा।

लेखे और संपरीक्षा

12. (1) आयोग समुचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रारूप में तैयार करेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा, विहित किया जाये।

(2) आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा, महालेखाकार, छत्तीसगढ़ द्वारा ऐसे अन्तरालों पर की जायेगी जो कि उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाये और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई भी व्यय आयोग द्वारा महालेखाकार को संदेय होगा।

वार्षिक रिपोर्ट

13. आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये ऐसे प्रारूप में तथा ऐसे समय पर, जो कि विहित किया जाये, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके कार्यकलापों का सम्पूर्ण विवरण दिया जायेगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षा रिपोर्ट का विधान सभा के समझ रखा जाना

14. राज्य सरकार वार्षिक रिपोर्ट को और उसके साथ आयोग द्वारा धारा 9 के अधीन दी गई सलाह पर की गई कार्रवाई और यदि ऐसी किसी सलाह को स्वीकार नहीं किया गया है तो ऐसे अस्वीकार किये जाने के कारणों का यदि कोई हो, एक ज्ञापन और संपरीक्षा रिपोर्ट को ऐसी रिपोर्टों के प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र, विधान सभा के समक्ष रखवायेगी।

अध्याय 5- प्रकीर्ण

आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी लोक सेवक होंगे

15. आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं.45) की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण

16. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही आयोग के किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।

नियम बनाने की शक्ति

17. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।
- (2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी विषय के लिये उपबंध हो सकेंगे, अर्थात्।
- (क) धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन और सदस्यों तथा धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन तथा भत्ते और सेवा संबंधी अन्य निबंध तथा शर्तें।
- (ख) धारा 12 की उपधारा (1) की अधीन वह प्रारूप, जिसमें लेखाओं का वार्षिक विवरण रिपोर्ट तैयार की जायेगी।
- (ग) धारा 13 के अधीन वह प्रारूप, जिसमें तथा वह समय जिसके भीतर वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी।

- (घ) कोई अन्य विषय जिसका विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाये
- (3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाये जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र विधान सभा के पटल पर रखा जायेगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

18. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।
- (2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, विधान सभा के पटल पर रखा जायेगा।

व्यावृति

19. छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1983 (क्रमांक 31 सन् 1983) के निरसन के होते हुये भी, अनुसूचित जनजातियों के संबंध में उक्त निरस्त अधिनियम के अधीन गठित आयोग द्वारा की गई किसी भी बात या कार्यवाही या उसकी सिफारिश के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा की गई किसी बात या कार्यवाही के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई है।

अटल नगर, दिनांक 15 अक्टूबर 2020

क्रमांक 7834/डी. 155/21-अ/ प्रारु./छ.ग. 20-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 15-10-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव

CHHATTISGARH ACT

(No. 22 OF 2020)

The Chhattisgarh Rajya Anusuchit Janjati Ayog

An Act further to amend the Chhattisgarh Rajya Anusuchit Janjati Ayog Adhiniyam, 1995 (No. 24 of 1995)

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-First year of the Republic of India as follows :

Chapter I - Preliminary

Short title Extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Rajya Anusuchit Janjati Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2020.
- (2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.
- (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Definitions

2. In The Act, Unless the context otherwise requires, -
 - (a) "Commission" means the Chhattisgarh Rajya Anusuchit Janjati Ayog Constituted under section 3.
 - (b) "Member" means a member of the Commission and includes the chairperson.
 - (c) "Scheduled Tribes" means such tribes, tribal communities or parts of, or groups within such tribes or tribal communities specified as Scheduled Tribes with respect to the State of Chhattisgarh under article 342 of the Constitution or India.

Chapter II - The State Commission for Anusuchit Janjati

Constitution of State Commission for Anusuchit Janjati

3. (1) The State Government shall constitute a body to be known as the Chhattisgarh Rajya anusuchit Janjati Ayog to exercise the power conferred on and to perform the functions assigned to it under this Act.
- (2) The Commission shall consist of the following members :-
 - (a) "Six non official members who have special knowledge in the matters relating to

Scheduled Tribes of whom one shall be the chairperson and one shall be the vice chairperson to be appointed by the State Government :

Provided that at least four members including the Chairperson and vice Chairperson, Shall be from amongst the Scheduled Tribes."

(b) Commissioner, Tribal Development, Chhattisgarh

Term of office and conditions of Service of Chairperson and Members

4. (1) "The Chairperson, Vice Chairperson and every member shall hold office, from the date on which he assumes the office, during the pleasure of the state Government."
- (2) A member may, by writing under his hand addressed to the State Government, resign from the office of Chairperson or as the case may be, of member at any time.
- (3) The State Government shall remove a person from the office of member if that person.
- (a) becomes an undischarged insolvent.
- (b) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which, in the opinion of the state Government, involves moral turpitude,
- (c) becomes of unsound mind and stands so declared by a competent court.
- (d) refuses to act or become incapable of acting.
- (e) is without obtaining leave of absence from the Commission, absent from three consecutive meetings of the Commission, or.
- (f) has in the opinion of the State Government, so abused the position of Chairperson of Member as to render his continuance in office detrimental to the interests of Scheduled Tribes or the public interest.
- Provided that no person shall be removed under this clause unless he has been given an opportunity of being heard in the matter.
- (4) A vacancy caused under sub-section(2) or otherwise shall be filled by fresh nomination and the person so nominated shall hold office for the remainder term of his predecessor.
- (5) The salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of service of the Chairperson and Members shall be such as may be prescribed.

Officers and other employees of the Commission

4. (1) The State Government shall a Secretary of the Commission and provided the Commission with such other officers and employees and may be necessary for the efficient performance of the functions of the Commission.
- (2) The salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of service of the officers and other employees appointed for the purpose of the commission shall be such as may be prescribed.

Salaries and allowances to the paid out a grant.

6. The salaries and allowances payable to the chairperson and members and the administrative expenses including salaries, allowance and pensions payable to the Secretary, officers and other employees referred to in Section 5 shall be paid out to the grants referred to in sub-section (1) of Section 11.

Vacancies, etc., not to invalidate proceedings of the Commission

7. No act pre proceeding of the Commission shall be invalid on the ground merely of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the Commission.

Procedure to be regulated by the Commission.

8. (1) The Commission shall meet as and when necessary at such time and place as the Chairperson may think fit.
- (2) The Commission shall regulate its own procedure.
- (3) All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the Secretary or any other officer of the Commission duly authorised by the Secretary in this behalf.

Chapter III-Functions and Powers of the Commission

Functions of the Commission

9. (1) It shall be function of the Commission-
 - (a) to act as watch-dog Commission for the protection afforded to the members of the Scheduled Tribes under the Constitution and under any other law for the time being in force,
 - (b) to recommend to the state Government to take steps to add particular tribes or tribal communities or parts of or groups within tribes or tribal communities in the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950

- (c) to watch the proper and timely implementation of programmes meant for welfare of Scheduled Tribes and to suggest improvement in such programmes of the State Government or any other body or authority responsible for such programmes.
 - (d) to tender advice regarding reservation for Scheduled Tribes in public services and admission in educational institutions.
 - (e) to perform such other functions as may be assigned to it by the State Government.
- (2) The advice of the Commission shall, ordinarily be binding upon the State Government, where, however, the Government does not accept the advice, it shall record its reason there for.

Power of the Commission

10. The Commission shall, while performing its functions under sub-section (I) of Section 9, have all the powers of a Civil Court trying a suit and in particular, in respect of the following matters namely:-
- (a) summoning and enforcing the attendance of any person from any part of the state and examining him on oath.
 - (b) requiring the discovery and production of any document.
 - (c) Receiving evidence on affidavits,
 - (d) requisitioning any public record or copy thereof from any court of office.
 - (e) issuing commission for the examination of witness and documents and.
 - (f) any other matter which may be prescribed.

Chapter IV - Finance, Accounts and audit

Grants by the State Government

11. (1) The Government shall, after due appropriation made by Legislative Assembly by law in this behalf, pay to the Commission by way of grants such sums of money as the State Government may think fit for being utilised for the purposes of this Act.
- (2) The Commission may spend such sums as it think fit for performing the functions under this act, and such sums shall be treated as expenditure payable out of the grants referred to in sub section (1)

Accounts and audit

12. (1) The Commission shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form as may be prescribed by the State Government.

- (2) The Accounts of the Commission shall be audited by the Accountant General of Chhattisgarh at such intervals as may be specified by him and any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the Commission to the Accountant General.

Annual Report

13. The Commission shall prepare, in such form and at such time for each financial year, as may be prescribed its annual report, giving a full accounts of its activities during the previous financial year and forward a copy thereof to the State Government.

Annual report and audit report to be laid before the Legislative Assembly-

14. The State Government shall cause the annual report, together with a memorandum of action taken on the advice tendered by the Commission under section 9 and the reason for the non-acceptance, if any of any such advice, and the audit report to be laid as soon as may be after they are received before the legislative Assembly.

Chapter V- Miscellaneous

Chairperson, Member, Officers and employees of the Commission to be public Servants.

15. The Chairperson, Members, Officers and employees of the Commission shall be deemed to be public servants within the meaning of Sections 21 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860)

Protection of action taken in good faith.

16. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any member, officer or employee of the Commission for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

Powers to make rules.

17. (1) The State Government may, by notification in the official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.
- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namely “-
- (a) salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of service of the Chairperson and Members under sub-section (5) of Section 4 and the

- Secretary, officers and other employees under-sub-section (2) of Section 5,
- (b) the form in which the annual statement of accounts shall be prepared under sub section (1) of Section 12 :
 - (c) the form in and the time at, which the annual report shall be prepared under Section 13.
 - (d) any other matter which is required to be, or may be prescribed.
 - (3) Every rule made under this Act shall be laid as soon as may after it is made on the table of the Lagislative Assembly.

Power to remover difficulties.

18. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make provision, not inconsistent with the provisions of this Act as appear to is to be necessary or expendent for removing difficulty.

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

- (2) Every order made under this section shall as soon as may be after it is made be laid on the table of the Lagislative Assembly.

Saving

19. Notwithstanding the repeal of the chhattisgarh Anusuchit Jati, Anusuchit Janjati Tatha Pichhada Varg Adhinyam, 1983, 1983 (No. 34 of 1983) anything done or any action taken in respect of Scheduled Tribes by the Commission constiuted under the said respect of Scheduled Tribes by the Commission constituted under the said repealad Act or by the State Government in pursuance of its recommendation shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of thi act.